

औपनिवेशिक एवं उत्तर-औपनिवेशिक भारत में कौशल शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण का ऐतिहासिक विकास

Historical Evolution of Skill Education and Technical Training in Colonial and Post-Colonial India

ज्योति रानी

Jyoti Rani

Research Scholar, Amity University, Haryana

jyotikasin96@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.22860662>

सारांश

कौशल शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण भारत की सामाजिक-आर्थिक संरचना, उत्पादन व्यवस्था और आजीविका के निर्माण में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रहे हैं। प्राचीन और पूर्व-औपनिवेशिक भारत में शिक्षा केवल शास्त्रीय या बौद्धिक ज्ञान तक सीमित नहीं थी, बल्कि अनेक समुदायों में कृषि, धातु-कर्म, वस्त्र-निर्माण, स्थापत्य, हस्तशिल्प, व्यापार, लेखांकन तथा अन्य व्यावहारिक व्यवसायों से संबंधित ज्ञान पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होता था। परिवार, समुदाय, श्रेणी तथा गुरु-शिष्य जैसी व्यवस्थाएँ कौशल के संरक्षण और प्रसार का महत्वपूर्ण माध्यम थीं। इस प्रकार ज्ञान और कर्म के बीच वह कठोर विभाजन नहीं दिखाई देता जो आधुनिक औपचारिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के बीच प्रायः देखने को मिलता है।

औपनिवेशिक शासन के विस्तार के साथ भारतीय शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अंग्रेजी माध्यम, साहित्यिक अध्ययन और प्रशासनिक आवश्यकताओं से जुड़ी शिक्षा को बढ़ती प्राथमिकता मिली, जबकि अनेक पारंपरिक कौशल और शिल्प; आर्थिक तथा संस्थागत दबावों के कारण हाशिए पर चले गए। औपनिवेशिक राज्य ने इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थानों की स्थापना भी की, किंतु उनका प्रारंभिक विकास मुख्यतः प्रशासन, सार्वजनिक निर्माण और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं से जुड़ा था। स्वतंत्रता के बाद नियोजित औद्योगिकीकरण, ITI, पॉलिटेक्निक तथा तकनीकी संस्थानों के विस्तार ने कौशल शिक्षा को नई दिशा दी, फिर भी सामान्य शिक्षा और रोजगार के बीच असंतुलन बना रहा।

यह शोध-पत्र औपनिवेशिक तथा उत्तर-औपनिवेशिक भारत में कौशल शिक्षा के ऐतिहासिक विकास का विश्लेषण करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP-2020) के संदर्भ में इसकी समकालीन प्रासंगिकता को स्पष्ट करता है। ऐतिहासिक-विश्लेषणात्मक पद्धति के माध्यम से किया गया यह अध्ययन यह समझने का प्रयास करता है कि शिक्षा, कौशल और रोजगार के बीच संबंध समय के साथ किस प्रकार परिवर्तित हुए। शोध का केंद्रीय तर्क यह है कि NEP-2020 में व्यावसायिक शिक्षा, स्थानीय कौशल, अनुभवात्मक अधिगम और बहुविषयक शिक्षा पर दिया गया बल भारत की दीर्घकालीन कौशल परंपराओं और आधुनिक आर्थिक आवश्यकताओं के बीच एक नया संवाद स्थापित करने का प्रयास है। पारंपरिक ज्ञान, आधुनिक तकनीक, डिजिटल दक्षता और उद्योग-शिक्षा सहयोग का संतुलित समन्वय समावेशी तथा सतत राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक है।

Abstract

Skill education and technical training have historically played an important role in shaping India's socio-economic structure, systems of production, and patterns of livelihood. In pre-colonial India,

learning was not confined to literary or intellectual instruction. Practical knowledge connected with agriculture, crafts, metallurgy, textiles, construction, trade, accounting, and other occupations was transmitted through families, communities, professional groups, and teacher-learner traditions. Such arrangements created a close relationship between knowledge, work, and everyday economic life.

Colonial rule introduced major changes in the organization and priorities of education. English-medium and literary education acquired increasing importance, particularly in relation to administrative requirements, while many indigenous systems of craft and vocational learning experienced economic and institutional marginalization. Technical institutions were also established under colonial rule, but their early objectives were closely connected with public works and the administrative needs of the colonial state. After independence, planned industrialization led to the expansion of Industrial Training Institutes, polytechnics, engineering education, and other forms of technical training. Nevertheless, the gap between formal education, employable skills, and changing labour-market requirements continued to remain a major challenge.

This paper traces the historical evolution of skill education from the pre-colonial and colonial periods to post-independence India and examines its relevance in the framework of the National Education Policy 2020 (NEP-2020). Using a historical-analytical approach based on policy documents and secondary scholarship, it examines the changing relationship between education, work, skills, and employment. The paper interprets the renewed emphasis on vocational exposure, experiential learning, multidisciplinary education, and local skills under NEP-2020 as an attempt to reconnect education with practical capabilities. It concludes that meaningful integration of indigenous knowledge, modern technology, digital competence, and industry-linked education is important for inclusive and sustainable national development.

मुख्यशब्द: कौशल शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण, औपनिवेशिक शिक्षा नीति, व्यावसायिक शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

Key words: Skill Education, Technical Training, Colonial Education Policy, Vocational Education, NEP-2020

परिचय

शिक्षा किसी भी समाज की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दिशा को निर्धारित करने वाला प्रमुख साधन होती है। यह केवल ज्ञान के संप्रेषण की प्रक्रिया नहीं, बल्कि व्यक्ति को समाज और उत्पादन व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाने योग्य बनाने का माध्यम भी है। भारत जैसे देश में, जहाँ कृषि, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग, व्यापार और विविध पेशागत गतिविधियाँ ऐतिहासिक रूप से आजीविका के मुख्य स्रोत रही हैं, कौशल-आधारित शिक्षा का विशेष महत्व रहा है। भारतीय समाज में अनेक प्रकार के व्यावहारिक ज्ञान का विकास स्थानीय आवश्यकताओं, उपलब्ध संसाधनों और समुदाय-आधारित अनुभव के आधार पर हुआ।

प्राचीन और पूर्व-औपनिवेशिक भारतीय शिक्षा में ज्ञान और कर्म के बीच पूर्ण पृथक्करण नहीं था। औपचारिक धार्मिक तथा साहित्यिक शिक्षा के अतिरिक्त अनेक कौशल परिवारों, समुदायों और पेशागत समूहों के माध्यम से सीखे जाते थे। शिल्पकार, बुनकर, धातु-कर्मी, कृषक, व्यापारी और अन्य पेशागत समुदाय अपने विशिष्ट ज्ञान को अगली पीढ़ियों तक पहुँचाते थे। इस व्यवस्था की अपनी सामाजिक सीमाएँ भी थीं, क्योंकि अनेक व्यवसाय जाति और वंशानुगत पेशों से जुड़े थे; फिर भी व्यावहारिक प्रशिक्षण उत्पादन और सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग था।

औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश शासन ने शिक्षा के संस्थागत स्वरूप और प्राथमिकताओं को प्रशासनिक तथा आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप पुनर्गठित किया।

अंग्रेजी शिक्षा और साहित्यिक अध्ययन के विस्तार ने आधुनिक उच्च शिक्षा के कुछ नए अवसर उत्पन्न किए, लेकिन औपचारिक शिक्षा और पारंपरिक व्यावसायिक प्रशिक्षण के बीच दूरी भी बढ़ी। साथ ही औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों, मशीन-निर्मित आयातित वस्तुओं और बदलती बाजार संरचना ने कई भारतीय हस्तशिल्पों और कुटीर उद्योगों पर दबाव डाला। इसलिए कौशल शिक्षा के इतिहास को केवल शैक्षिक नीति के इतिहास के रूप में नहीं, बल्कि व्यापक आर्थिक परिवर्तन के संदर्भ में देखना आवश्यक है।

स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्य ने नियोजित विकास और औद्योगिकीकरण को राष्ट्र-निर्माण की प्रमुख रणनीति के रूप में अपनाया। तकनीकी मानव संसाधन तैयार करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निकों का विस्तार किया गया। इसके बावजूद सामान्य शिक्षा की प्रतिष्ठा और व्यावसायिक शिक्षा के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण के बीच अंतर बना रहा। रोजगार बाजार में तकनीकी परिवर्तन के कारण नई दक्षताओं की मांग लगातार बढ़ती गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसी दीर्घ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में शिक्षा और कौशल को अधिक निकट लाने, व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा से जोड़ने तथा अनुभवात्मक और बहुविषयक अधिगम को प्रोत्साहित करने का प्रयास प्रस्तुत करती है।

साहित्य समीक्षा

कौशल और शिक्षा के ऐतिहासिक संबंध को समझने के लिए भारतीय शिक्षा के इतिहास, औपनिवेशिक नीतियों, मानव क्षमता तथा आधुनिक कौशल-विकास से संबंधित साहित्य का संयुक्त अध्ययन आवश्यक है। ए. एस. अल्टेकर [1] प्राचीन भारतीय शिक्षा की संस्थाओं, उद्देश्यों और शिक्षण परंपराओं को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक अध्ययन है। उनके विवेचन से यह संकेत मिलता है कि शिक्षा का संबंध नैतिक और बौद्धिक निर्माण के साथ जीवनोपयोगी गतिविधियों से भी था।

सैयद नुरुल्लाह एवं अन्य [2] का अध्ययन औपनिवेशिक शिक्षा के विकास को व्यापक ऐतिहासिक

संदर्भ में रेखांकित करता है। यह साहित्य ब्रिटिश नीतियों, अंग्रेजी शिक्षा, आधुनिक विद्यालयी संस्थाओं और भारतीय समाज की आवश्यकताओं के बीच उत्पन्न तनाव को समझने में उपयोगी है। औपनिवेशिक शिक्षा के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि आधुनिक संस्थाओं के विकास के साथ-साथ शिक्षा का स्वरूप प्रशासनिक और प्रमाणपत्र-केंद्रित भी होता गया।

अपर्णा बसु [3] शिक्षा और राजनीतिक विकास के संबंध को रेखांकित करती हैं। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा राष्ट्र-निर्माण, सामाजिक गतिशीलता और आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण माध्यम बनी। दूसरी ओर अमर्त्य सेन [4] का अध्ययन भारतीय बौद्धिक परंपराओं की विविधता को सामने लाता है और व्यापक अर्थ में शिक्षा तथा मानवीय क्षमताओं के महत्व को समझने में सहायता करता है। कौशल शिक्षा को केवल रोजगार प्राप्त करने की तकनीक के रूप में नहीं, बल्कि व्यक्ति की क्षमताओं, विकल्पों और उत्पादक भागीदारी को विकसित करने के साधन के रूप में देखना अधिक उपयोगी है।

UNESCO और ILO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अध्ययनों में आधुनिक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में तकनीकी, व्यावसायिक और हस्तांतरणीय कौशलों की आवश्यकता पर बल दिया गया है। डिजिटल परिवर्तन, स्वचालन, सेवा क्षेत्र का विस्तार और बदलती कार्य-प्रकृति ने आजीवन अधिगम तथा पुनःकौशल (reskilling) की आवश्यकता को बढ़ाया है। विज्ञान प्रकाश में प्रकाशित संदर्भित लेख भारतीय ज्ञान परंपरा, वैज्ञानिक लेखन, पारिभाषिक शब्दावली और ज्ञान की सामाजिक उपयोगिता से संबंधित विमर्श को आधार प्रदान करते हैं।

उपलब्ध साहित्य का समग्र अध्ययन बताता है कि प्राचीन शिक्षा, औपनिवेशिक शिक्षा नीति, स्वतंत्र भारत की शिक्षा व्यवस्था और समकालीन कौशल नीति पर पर्याप्त अध्ययन उपलब्ध हैं; किंतु इन सभी चरणों को एक निरंतर ऐतिहासिक प्रक्रिया के रूप में जोड़ते हुए कौशल शिक्षा के परिवर्तन को समझने की गुंजाइश बनी हुई है। प्रस्तुत अध्ययन इसी ऐतिहासिक-नीतिगत निरंतरता को केंद्र में रखता है।

औपनिवेशिक भारत में कौशल शिक्षा

औपनिवेशिक भारत में शिक्षा की दिशा ब्रिटिश प्रशासनिक हितों, मिशनरी गतिविधियों, भारतीय समाज के भीतर आधुनिक शिक्षा की बढ़ती मांग और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के परिवर्तन से प्रभावित हुई। 1835 से जुड़ी मैकाले की प्रसिद्ध शिक्षा संबंधी टिप्पणी तथा उसके बाद अंग्रेजी शिक्षा को मिली प्राथमिकता ने साहित्यिक और प्रशासनिक शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया। इसका प्रभाव यह हुआ कि सरकारी नौकरियों के लिए औपचारिक शिक्षा और अंग्रेजी ज्ञान की उपयोगिता बढ़ी।

इस परिवर्तन को पारंपरिक कौशलों के आर्थिक संकट से अलग करके नहीं देखा जा सकता। भारतीय हस्तशिल्प और कुटीर उत्पादन को मशीन-निर्मित वस्तुओं, औपनिवेशिक व्यापार संरचना तथा बाजार में बदलाव से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। अनेक कारीगरों और दस्तकारों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई। फलतः परिवार और समुदाय आधारित कौशल-हस्तांतरण की कुछ पारंपरिक व्यवस्थाओं पर भी दबाव पड़ा। यह प्रक्रिया सभी क्षेत्रों और व्यवसायों में समान नहीं थी; कई स्थानीय शिल्प बदलती परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित भी हुए।

औपनिवेशिक शासन ने तकनीकी प्रशिक्षण को पूरी तरह उपेक्षित नहीं किया। सार्वजनिक निर्माण, सर्वेक्षण, सिंचाई, रेलवे तथा अन्य प्रशासनिक आवश्यकताओं ने प्रशिक्षित तकनीकी कर्मियों की मांग उत्पन्न की। रुड़की में स्थापित इंजीनियरिंग संस्था इस दिशा का महत्वपूर्ण उदाहरण बनी। किंतु ऐसे संस्थानों का प्रारंभिक उद्देश्य व्यापक जनसमुदाय के लिए कौशल-आधारित आत्मनिर्भर शिक्षा स्थापित करना नहीं, बल्कि औपनिवेशिक राज्य की विशिष्ट तकनीकी और प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करना था।

उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी के दौरान भारतीय चिंतकों, समाज सुधारकों और राष्ट्रवादी नेतृत्व में ऐसी शिक्षा की आवश्यकता पर चर्चा बढ़ी जो भारतीय समाज की वास्तविक आवश्यकताओं, उत्पादन और स्वावलंबन से जुड़ी हो। इस प्रकार औपनिवेशिक काल में एक ओर साहित्यिक-प्रशासनिक शिक्षा का विस्तार

हुआ और दूसरी ओर व्यावहारिक, औद्योगिक तथा राष्ट्रीय शिक्षा के वैकल्पिक विचार भी विकसित हुए। यही बहस आगे स्वतंत्र भारत में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के संस्थागत विस्तार की पृष्ठभूमि बनी।

उत्तर-औपनिवेशिक भारत में कौशल शिक्षा

1947 के बाद भारत के सामने आर्थिक पुनर्निर्माण, औद्योगिकीकरण, रोजगार सृजन और प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने की बड़ी चुनौती थी। नियोजित विकास के अंतर्गत भारी उद्योग, आधारभूत संरचना, ऊर्जा, परिवहन और सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार के लिए तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता बढ़ी। पंचवर्षीय योजनाओं ने तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण को विकास प्रक्रिया से जोड़ने का प्रयास किया।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) और पॉलिटेक्निक कॉलेज इस संरचना के महत्वपूर्ण अंग बने। ITI का उद्देश्य विभिन्न औद्योगिक ट्रेडों के लिए प्रशिक्षित कार्यबल तैयार करना था, जबकि पॉलिटेक्निक संस्थानों ने डिप्लोमा स्तर पर तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराई। इंजीनियरिंग शिक्षा के विस्तार ने उच्च स्तर के तकनीकी मानव संसाधन के निर्माण में योगदान दिया। 1960 और 1970 के दशकों में इन संस्थानों का विस्तार हुआ, किंतु देश की विशाल और बढ़ती जनसंख्या तथा क्षेत्रीय असमानताओं के कारण प्रशिक्षण की उपलब्धता और गुणवत्ता समान नहीं रही।

स्वतंत्र भारत में एक महत्वपूर्ण समस्या सामान्य अकादमिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के बीच सामाजिक प्रतिष्ठा का अंतर भी रही। बड़ी संख्या में विद्यार्थी सामान्य डिग्रियों की ओर आकर्षित हुए, जबकि कौशल-आधारित प्रशिक्षण को कई बार द्वितीयक विकल्प के रूप में देखा गया। परिणामस्वरूप डिग्री प्राप्त करने के बावजूद रोजगार के लिए आवश्यक व्यावहारिक दक्षताओं की कमी और दूसरी ओर उद्योगों को प्रशिक्षित श्रमिकों की आवश्यकता-दोनों स्थितियाँ साथ-साथ दिखाई दीं।

1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक बाजार, निजी निवेश, सूचना

प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र से जुड़ाव तेजी से बढ़ा। इससे रोजगार की प्रकृति और कौशल की मांग में परिवर्तन आया। कंप्यूटर दक्षता, संचार कौशल, तकनीकी अनुकूलन, सेवा-क्षेत्र की क्षमता और बाद में डिजिटल कौशल अधिक महत्वपूर्ण होते गए। इस परिवर्तन ने कौशल शिक्षा को केवल औद्योगिक ट्रेडों तक सीमित रखने के बजाय व्यापक रोजगार-क्षमता से जोड़ने की आवश्यकता पैदा की।

इक्कीसवीं सदी में कौशल विकास को राष्ट्रीय विकास रणनीति के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में अधिक स्पष्ट स्थान मिला। इसके बावजूद प्रशिक्षण की गुणवत्ता, उद्योग की वास्तविक मांग से पाठ्यक्रम का संबंध, प्रशिक्षकों की उपलब्धता, ग्रामीण-शहरी अंतर और कौशल प्रमाणन जैसे मुद्दे बने रहे। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में NEP-2020 व्यावसायिक शिक्षा को विद्यालय और उच्च शिक्षा की मुख्यधारा के साथ अधिक व्यवस्थित रूप से जोड़ने की दिशा प्रस्तुत करती है।

शोध अंतराल

उपलब्ध अध्ययनों में भारतीय शिक्षा के इतिहास, औपनिवेशिक शिक्षा नीति, औद्योगिक प्रशिक्षण, तकनीकी शिक्षा और समकालीन कौशल-विकास नीतियों पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। फिर भी इन विषयों का अध्ययन प्रायः अलग-अलग कालखंडों अथवा अलग-अलग नीति क्षेत्रों में किया जाता है। परिणामस्वरूप पूर्व-औपनिवेशिक कौशल परंपराओं, औपनिवेशिक शिक्षा के पुनर्गठन, स्वतंत्र भारत के संस्थागत तकनीकी प्रशिक्षण और वर्तमान व्यावसायिक शिक्षा नीति के बीच ऐतिहासिक संबंध हमेशा स्पष्ट रूप से सामने नहीं आता।

दूसरा महत्वपूर्ण अंतराल शिक्षा और रोजगार के बीच दीर्घकालीन असंतुलन के ऐतिहासिक कारणों से संबंधित है। केवल वर्तमान बेरोजगारी या skill gap का अध्ययन यह नहीं बताता कि सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के बीच सामाजिक तथा संस्थागत दूरी किस प्रकार विकसित हुई। इस शोध का प्रयास इन प्रक्रियाओं को ऐतिहासिक क्रम में रखकर समझना है।

प्रस्तुत अध्ययन इस अंतराल को भरते हुए कौशल शिक्षा को भारतीय शिक्षा के इतिहास की एक निरंतर, किंतु बदलती हुई धारा के रूप में देखता है। इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि NEP-2020 के अंतर्गत कौशल और व्यावसायिक शिक्षा पर दिया गया बल वर्तमान आर्थिक आवश्यकताओं की प्रतिक्रिया होने के साथ-साथ शिक्षा और कार्य के ऐतिहासिक रूप से कमजोर हुए संबंध को पुनः स्थापित करने का प्रयास भी माना जा सकता है।

शोध पद्धति

यह अध्ययन मुख्यतः ऐतिहासिक-विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है। इसका उद्देश्य विभिन्न ऐतिहासिक चरणों में कौशल शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण के स्वरूप, उद्देश्य तथा संस्थागत परिवर्तन का विश्लेषण करना है। अध्ययन में कालानुक्रमिक दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसके माध्यम से पूर्व-औपनिवेशिक परंपराओं, औपनिवेशिक शिक्षा, स्वतंत्रता के बाद के तकनीकी विकास और NEP-2020 तक की प्रवृत्तियों को परस्पर संबंधित रूप में देखा गया है।

प्राथमिक स्रोतों की श्रेणी में शिक्षा संबंधी नीतिगत दस्तावेज और सरकारी सामग्री को आधार बनाया गया है। विशेष रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समकालीन नीति विश्लेषण का प्रमुख दस्तावेज है। द्वितीयक स्रोतों में शिक्षा के इतिहास से संबंधित मानक पुस्तकें, शोध-लेख और UNESCO तथा ILO जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्टें सम्मिलित हैं।

स्रोतों के अध्ययन में वर्णनात्मक विवरण के साथ तुलनात्मक विश्लेषण का प्रयोग किया गया है। अलग-अलग कालखंडों में शिक्षा के उद्देश्य, कौशल की स्थिति और रोजगार से उसके संबंध की तुलना की गई है। अध्ययन का स्वरूप मुख्यतः गुणात्मक है; इसका उद्देश्य किसी एक कार्यक्रम के सांख्यिकीय प्रभाव का मापन करने के बजाय दीर्घकालीन ऐतिहासिक परिवर्तन और नीति-परिवर्तन को समझना है।

डेटा विश्लेषण/सारणीबद्ध प्रस्तुतीकरण

विभिन्न कालखंडों में शिक्षा और कौशल के संबंध को संक्षेप में निम्न सारणी के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है:

कालखंड	शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य	कौशल शिक्षा की स्थिति
प्राचीन/पूर्व-औपनिवेशिक भारत	जीवनोपयोगी, बौद्धिक एवं सामाजिक शिक्षा	कई क्षेत्रों में समुदाय और पेशागत परंपराओं से जुड़ी कौशल-केंद्रित व्यवस्था
औपनिवेशिक काल	साहित्यिक शिक्षा तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति	पारंपरिक कौशलों पर आर्थिक दबाव सीमित संस्थागत तकनीकी प्रशिक्षण
उत्तर-स्वतंत्र भारत	औद्योगिक विकास, राष्ट्र-निर्माण और प्रशिक्षित मानव संसाधन	ITI, पॉलिटेक्निक और तकनीकी संस्थानों के माध्यम से आंशिक पुनरुद्धार और विस्तार
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020	समग्र, बहुविषयक, अनुभवात्मक एवं रोजगार-संबद्ध शिक्षा	व्यावसायिक शिक्षा और कौशल को मुख्यधारा से जोड़ने पर बल

सारणी से स्पष्ट होता है कि कौशल शिक्षा की भूमिका विभिन्न कालखंडों में समान नहीं रही। पूर्व-औपनिवेशिक व्यवस्था में कौशल अनेक सामाजिक और पेशागत संरचनाओं के भीतर अंतर्निहित था। औपनिवेशिक काल में औपचारिक शिक्षा की प्राथमिकताएँ बदलने तथा आर्थिक संरचना के परिवर्तन से पारंपरिक कौशल व्यवस्था पर दबाव बढ़ा। स्वतंत्रता के बाद राज्य ने तकनीकी प्रशिक्षण को संस्थागत आधार दिया, जबकि NEP-2020 में कौशल को सामान्य शिक्षा के साथ अधिक व्यापक रूप से एकीकृत करने की दिशा दिखाई देती है।

यह तुलना यह भी संकेत करती है कि आधुनिक कौशल नीति को केवल रोजगार कार्यक्रम के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है। कौशल की सामाजिक प्रतिष्ठा, शिक्षा प्रणाली में उसका स्थान, उद्योग से संबंध तथा स्थानीय ज्ञान की उपयोगिता—ये सभी पहलू दीर्घकालीन ऐतिहासिक विकास से जुड़े हैं। इसलिए वर्तमान नीति की सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि कौशल शिक्षा को विद्यार्थियों के लिए समान रूप से सम्मानजनक और प्रगतिशील शैक्षिक विकल्प बनाया जा सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और कौशल शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था

को अधिक समग्र, लचीला, बहुविषयक और अनुभवात्मक बनाने की दिशा प्रस्तुत करती है। कौशल शिक्षा के संदर्भ में इसका महत्व इस बात में है कि यह व्यावसायिक शिक्षा को केवल अलग प्रशिक्षण व्यवस्था के रूप में न देखकर विद्यालयी और उच्च शिक्षा के व्यापक ढाँचे के साथ जोड़ने पर बल देती है। इससे सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा के बीच लंबे समय से बनी सामाजिक तथा संस्थागत दूरी को कम करने की संभावना उत्पन्न होती है।

नीति विद्यालय स्तर से व्यावसायिक exposure और अनुभवात्मक अधिगम को प्रोत्साहित करती है। स्थानीय व्यवसायों, कारीगरों, शिल्प और कार्य-अनुभव से परिचय विद्यार्थियों को श्रम, उत्पादन और कौशल की वास्तविक दुनिया से जोड़ सकता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को कम आयु में किसी एक पेशे में बाँधना नहीं, बल्कि उन्हें विभिन्न प्रकार के कार्य, तकनीक और कौशल के प्रति परिचित तथा सम्मानपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करना है।

उच्च शिक्षा में बहुविषयक संरचना, लचीले पाठ्यक्रम और बहु-प्रवेश/निकास की अवधारणा कौशल-आधारित अधिगम को नए अवसर प्रदान करती है। यदि अकादमिक अध्ययन के साथ व्यावहारिक

परियोजनाएँ, इंटरशिप, डिजिटल कौशल और उद्योग से संपर्क प्रभावी रूप से जोड़े जाएँ, तो शिक्षा और रोजगार के बीच संबंध मजबूत हो सकता है। हालांकि नीति के उद्देश्यों और वास्तविक परिणामों के बीच अंतर कार्यान्वयन की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा।

ऐतिहासिक दृष्टि से NEP-2020 का महत्व यह है कि यह ज्ञान और कौशल को परस्पर विरोधी श्रेणियों में रखने के बजाय उनके एकीकरण की दिशा में विचार करती है। भारतीय कौशल परंपराओं की उपयोगी विशेषताओं को आधुनिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी और बाजार की आवश्यकताओं से जोड़ना तभी सार्थक होगा जब स्थानीय ज्ञान को केवल प्रतीकात्मक रूप से नहीं, बल्कि पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण, अनुसंधान और उद्यमिता से वास्तविक रूप में जोड़ा जाए।

इसके साथ कुछ चुनौतियाँ भी महत्वपूर्ण हैं—प्रशिक्षित शिक्षकों और प्रशिक्षकों की उपलब्धता, पर्याप्त प्रयोगशालाएँ और कार्यशालाएँ, उद्योग के साथ स्थायी साझेदारी, ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधन, विद्यार्थियों की सामाजिक आकांक्षाएँ तथा कौशल पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता। अतः NEP-2020 की कौशल संबंधी दृष्टि का प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि नीति को संस्थागत स्तर पर किस प्रकार लागू किया जाता है।

संभावित अनुप्रयोग

- **आत्मनिर्भर भारत को सशक्त आधार:** स्थानीय उत्पादन, तकनीकी दक्षता, उद्यमिता और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण को मजबूत करके कौशल शिक्षा आत्मनिर्भरता की व्यापक अवधारणा को व्यावहारिक आधार प्रदान कर सकती है। प्रशिक्षित युवा केवल नौकरी तलाशने वाले न रहकर उत्पादन, सेवा और उद्यमिता में भी भागीदारी कर सकते हैं।

- **स्थानीय कौशल का पुनरुत्थान:** भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विकसित हस्तशिल्प, वस्त्र, कृषि—आधारित कौशल और अन्य पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक डिजाइन, गुणवत्ता नियंत्रण, डिजिटल विपणन और तकनीकी नवाचार से जोड़कर उनकी आर्थिक उपयोगिता बढ़ाई जा सकती है।

- **उद्योग-शिक्षा सहयोग:** शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों के बीच इंटरशिप, अप्रेंटिसशिप, संयुक्त प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम परामर्श और प्रयोगात्मक परियोजनाएँ विद्यार्थियों को वास्तविक कार्य परिस्थितियों से परिचित करा सकती हैं। इससे प्रशिक्षण और रोजगार बाजार की आवश्यकताओं के बीच अंतर कम करने में सहायता मिल सकती है।

- **युवाओं की रोजगार-क्षमता में वृद्धि:** विषयगत ज्ञान के साथ तकनीकी, डिजिटल, संचार, समस्या-समाधान और कार्यस्थल संबंधी कौशल विकसित करने से युवाओं की रोजगार-क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। विशेष रूप से तेजी से बदलती तकनीक के संदर्भ में आजीवन अधिगम और पुनःकौशल की क्षमता महत्वपूर्ण होगी।

निष्कर्ष एवं भविष्य की दिशा

यह अध्ययन दर्शाता है कि कौशल शिक्षा भारत की ऐतिहासिक विरासत और सामाजिक-आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण अंग रही है। विभिन्न कालखंडों में इसके संस्थागत रूप, सामाजिक स्थिति और आर्थिक भूमिका में परिवर्तन आया। पूर्व-औपनिवेशिक समाज में अनेक कौशल, उत्पादन और समुदाय-आधारित ज्ञान प्रणालियों में अंतर्निहित थे। औपनिवेशिक काल में शिक्षा की नई प्राथमिकताओं और आर्थिक परिवर्तन ने इस संबंध को पुनर्गठित किया। आधुनिक तकनीकी संस्थाओं का विकास हुआ, किंतु पारंपरिक कौशल और औपचारिक शिक्षा के बीच दूरी भी बढ़ी।

स्वतंत्रता के बाद नियोजित औद्योगिकीकरण ने तकनीकी शिक्षा को राष्ट्र-निर्माण की आवश्यकताओं से जोड़ा। ITI, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग संस्थानों के विस्तार से प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। फिर भी सामान्य शिक्षा और रोजगार के बीच असंतुलन, व्यावसायिक शिक्षा की अपेक्षाकृत कम सामाजिक प्रतिष्ठा, प्रशिक्षण की गुणवत्ता और उद्योग की आवश्यकताओं से पाठ्यक्रम के संबंध जैसी समस्याएँ बनी रहीं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इन ऐतिहासिक चुनौतियों के संदर्भ में कौशल शिक्षा को मुख्यधारा से जोड़ने की

दिशा प्रस्तुत करती है। व्यावसायिक exposure, अनुभवात्मक शिक्षा, स्थानीय कौशलों से जुड़ाव और बहुविषयक संरचना ऐसे तत्व हैं जो ज्ञान और कार्य के बीच संबंध को अधिक सुदृढ़ कर सकते हैं। फिर भी नीति की सफलता केवल उसके प्रावधानों से नहीं, बल्कि संसाधनों, प्रशिक्षकों, संस्थागत क्षमता, उद्योग सहयोग और सामाजिक स्वीकार्यता से निर्धारित होगी।

भविष्य के शोध में क्षेत्रीय कौशल परंपराओं, ग्रामीण और शहरी प्रशिक्षण के अंतर, लैंगिक भागीदारी, डिजिटल तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण बदलती रोजगार संरचना, अप्रेंटिसशिप, स्थानीय उद्योग और उच्च शिक्षा संस्थानों के सहयोग जैसे विषयों का अधिक गहन अध्ययन किया जा सकता है। विभिन्न राज्यों और प्रशिक्षण संस्थानों के तुलनात्मक अध्ययन से यह समझने में सहायता मिलेगी कि कौन-सी संस्थागत व्यवस्थाएँ कौशल शिक्षा को रोजगार और उद्यमिता से प्रभावी रूप से जोड़ती हैं।

अंततः भारत की कौशल नीति के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिशा पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक को परस्पर विरोधी मानने के बजाय उनका उपयोगी समन्वय करना है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था, जो बौद्धिक विकास के साथ व्यावहारिक क्षमता, तकनीकी दक्षता,

नवाचार और श्रम के सम्मान को विकसित करे, समावेशी तथा सतत राष्ट्रीय विकास के लिए अधिक उपयोगी आधार प्रदान कर सकती है।

संदर्भ

1. Altekar, A. S., Education in Ancient India, 1944.
2. Nurullah, S., and Naik, J. P., History of Education in India, 1951.
3. Basu, A., Growth of Education and Political Development in India, 1982.
4. Sen, A., The Argumentative Indian, 2005.
5. Government of India, National Education Policy 2020, 2020.
6. UNESCO, Global Report on Skills Development, 2019.
7. ILO, Skills and the Future of Work, 2020.
8. ओम विकास, "वैज्ञानिक शोध लेखन: अभ्यास और स्वाभिमान का संतुलन", विज्ञान प्रकाश, 2022.
9. रघुवीर, "परिभाषिक शब्दावली निर्माण के सिद्धांत", विज्ञान प्रकाश, 2022.